



## वर्ष 2022-27 के लिये राष्ट्रीय वदियुत योजना

### प्रलिमिंस के लिये:

केंद्रीय वदियुत प्राधकिरण, वदियुत अधनियिम, 2003, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, लधियिम-आयन बैटरी ।

### मेन्स के लिये:

वर्ष 2022-27 के लिये राष्ट्रीय वदियुत योजना ।

## चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय वदियुत योजना (**National Electricity Plan- NEP**) का नवीनतम मसौदा वर्ष 2022-27 की अवधि को कवर करता है, जो इसके पछिले संस्करण, जसिमें मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रति कथिा गया था, में एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है ।

## राष्ट्रीय वदियुत योजना:

### परचिय:

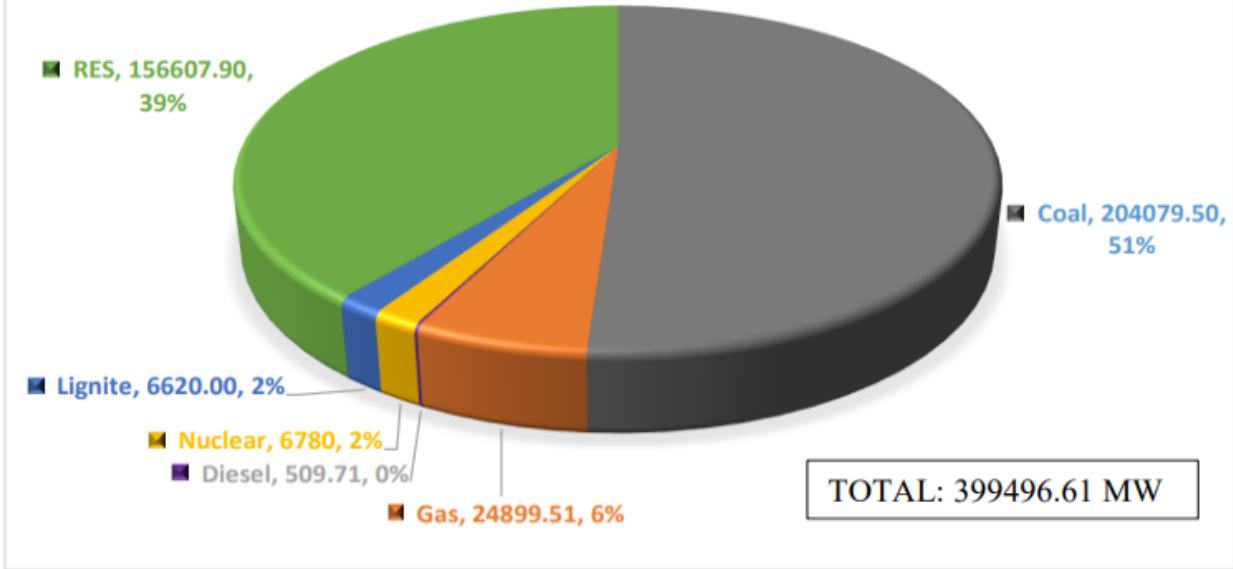
- NEP एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो भारत में वदियुत क्षेत्र के विकास का मार्गदर्शन करता है । यह वदियुत अधनियिम, 2003 के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष में **केंद्रीय वदियुत प्राधकिरण (CEA)** द्वारा तैयार कथिा जाता है ।
- CEA योजना क्षमता वृद्धि की मांग का आकलन करने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये वभिन्न योजना हेतु एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करने के लिये अल्पकालिक (5 वर्ष) और संभावति योजनाएँ (15 वर्ष) तैयार करता है ।
- NEP पछिले पाँच वर्षों (2017-22) के अनुमानों की समीक्षा, वर्ष 2022-27 के लिये क्षमता वृद्धि आवश्यकता और वर्ष 2027-2032 की अवधि के लिये अनुमान प्रदान करता है ।
- पहला NEP वर्ष 2007 में, दूसरा दसिंबर 2013 में और तीसरा 2018 में प्रकाशति हुआ था, जसिमें 2017-22 की व्यापक योजना एवं 2022-27 की संभावति योजना शामिल थी ।

### नया मसौदा:

- यह वर्ष 2031-32 तक 17 GW से लेकर लगभग 28 GW तक की अतिरिक्त कोयला-आधारति क्षमता की आवश्यकता को उजागर करता है, जो वर्तमान में नरिमाणाधीन 25 GW कोयला-आधारति क्षमता से अधिक है ।
- मसौदा योजना में वर्ष 2031-32 तक 51 GW से 84 GW के बीच अनुमानति आवश्यकता के साथ बैटरी भंडारण में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है ।
- इससे कोयले से चलने वाले वदियुत संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर (PLF) वर्ष 2026-27 के 55% से बढ़कर 2031-32 में 62% हो जाएगा ।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ती नरिभरता से उत्पन्न चुनौतियों पर भी ज़ोर देता है, जसिके लिये आने वाले वर्षों में सावधानीपूर्वक प्रबंधन एवं योजना की आवश्यकता होगी ।

## भारत का वदियुत शक्ति परिदृश्य:

## ALL INDIA INSTALLED CAPACITY AS ON 31.03.2022 (ALL VALUES ARE IN MW)



//

### संबंधित चुनौतियाँ:

- पुराने संयंत्रों पर निर्भरता:
  - भारत के कोयले से चलने वाले ताप वद्युत संयंत्र 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं, साथ ही पुरानी तकनीक पर पर्याप्त निवेश और वद्युत पूर्ति संबंधी चिंता पैदा करता है।
- नवीकरणीय-प्रभुत्व (Renewables-Dominated) वाले ग्रिड का प्रबंधन कठिन:
  - क्षमता वृद्धि की पूर्णता के लिये नवीकरणीय उत्पादन पर निर्भरता रही है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि ग्रिड का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। सौर और पवन ऊर्जा की धीमी वृद्धि के साथ-साथ शून्य ऊर्जा वाले जलवद्युत परियोजनाओं के कारण ग्रिड को स्थिरता प्रदान करने की गति में कमी आई है।
- अपर्याप्त वित्तीयन:
  - यदि नवीकरणीय उत्पादन के बैकअप के लिये बैटरी भंडारण पर निर्भर रहना है, तो इसके लिये महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।
    - CEA की रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2022-27 के बीच बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिसिस्टम्स (BESS) के लिये कुल 14.30 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हालाँकि CEA ने 10 वर्ष की अवधि के लिये BESS के विकास के लिये केवल 8 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है।
- मूल्यांकन की कमी:
  - वभिन्न सौर उत्पादन परदृश्यों के तहत तापीय संयंत्रों के लिये रैपिड दर संबंधी कोई मूल्यांकन नहीं है।
    - रैपिड दर वह दर है जिस पर एक वद्युत संयंत्र अपने उत्पादन को बढ़ा अथवा घटा सकता है।
    - उचित मूल्यांकन के बिना ओवरलोडिंग, अंडरलोडिंग अथवा वद्युत की रुकावट जैसी समस्या हो सकती है।

### संबंधित चुनौतियों का समाधान:

- लघु-आयन बैटरी पर आधारित BESS लोड में उतार-चढ़ाव और उत्पादन में अंतर के खिलाफ ग्रिड को संतुलित करने हेतु एक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। ऊर्जा भंडारण ऊर्जा समय-स्थानांतरण प्रदान कर सकता है, जिससे वद्युत का उपयोग तब किया जा सकता है जब इसकी आवश्यकता होती है।
- बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश जारी रखने के साथ-साथ जल-आधारित प्रणालियों जैसे नए समाधानों की खोज करना महत्वपूर्ण है। यह वर्ष 2022-27 के लिये राष्ट्रीय वद्युत योजना में उल्लिखित चुनौतियों का समाधान करने तथा भारत में एक स्थिर और वश्वसनीय वद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
- इसके अतिरिक्त हाइब्रिड उत्पादन मॉडल के उपयोग को बढ़ाने से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करने में मदद मिलेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर बैकअप पावर उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा।

### स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

